Regarding closure of ITIs ? laid

श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे (रावेर): DGT ने 2018 से 2022 तक आई टी आई ट्रेड्स/यूनिट्स में जीरो एडमिशन किए है । ऐसी सभी संस्थाओं को बंद तथा DGT आफ़ीलीएशन रद्द करने हेतु सर्वे करने के लिए सभी राज्यों को सूचित किया है । इन गत पांच वर्षों में 30000 आई टी आई ट्रेड्स/यूनिट्स जो DGT आफीलीएशन प्राप्त थे, बंद हुए हैं ऐसे यूनिट्स बंद होने से करीब करीब 6.5 लाख से भी ज्यादा विद्यार्थियों को इस लाभ से वंचित रहना पड़ा है । अनेक वर्षों से आधारभूत सुविधा स्वयं पूंजी/सोर्सेज से जमा कर आई टी आई ट्रेड्स/यूनिट्स प्राइवेट संस्था का निर्माण पूरे देश में हुआ है जिसका लाभ गरीब तथा ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को गत अनेक वर्षों से होता दिखता है । इन सभी आई टी आई संस्थाओं को कोई सरकारी अनुदान/सहायता किसी भी प्रकार से कभी भी उपलब्ध नहीं थी । ऐसी संस्थाएं अगर इस DGT की नई पॉलिसी प्रस्तावित होने से बंद होती है तो गरीब तथा ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों हेतु स्वयं-रोजगार निर्मित करने का यह प्रभावी साधन है और इससे इन गरीब परिवारों का बड़ी मात्रा में नुकसान होगा तथा इन संस्थाओं से जुड़े/प्राप्त अनेक व्यक्ति बेरोजगार हो सकते है, अकेले महाराष्ट्र राज्य में इन संस्थाओं से जुड़े करीब करीब 10000 से ज्यादा लोक/परिवार संस्थाएं बंद होने से बेरोजगार/बेघर हो सकते है । मेरा सरकार से तथा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि यह पॉलिसी कार्यान्वित करने के बारे में पुनर्विचार करें जो अभी सर्वे की स्टेज पर है और इन संस्थाओं को कुछ ज्यादा समय इस स्थिति को सुधार करने के लिए उपलब्ध करायें ।